

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
26.03.2025 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 4356 का उत्तर

### रेलवे में नियंत्रित पहुंच प्रणाली की शुरुआत

4356. श्री सुधाकर सिंहः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की मेट्रो रेल नेटवर्क की तरह रेलवे में नियंत्रित पहुंच प्रणाली शुरू करने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो इसकी व्यवहार्यता और कार्यान्वयन की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या नियंत्रित पहुंच के लिए कोई पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं;
- (घ) यदि हां, तो रेलवे जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) व्यस्ततम् घंटों और त्यौहारों के मौसम के दौरान प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): त्यौहार/मेला अवधि के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की अत्यधिक भारी भीड़ को संभालने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा सीमित प्रवेश नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया गया है जहां ऐसे समय के दौरान, स्टेशनों के बाहर होलिडंग क्षेत्र बनाए गए थे और यात्रियों को केवल तभी अनुमति दी गई जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई थी।

इसके अलावा, स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ की सम्हालाई के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. 60 स्टेशनों पर स्थायी होलिडंग क्षेत्रः

- 2024 के त्यौहारों के दौरान, स्टेशनों के बाहर होलिडंग क्षेत्र बनाए गए। ये प्रतीक्षालय सूरत उधना, पटना और नई दिल्ली में भारी भीड़ को संभालने में सक्षम थे। यात्रियों को केवल तब अनुमति दी गई जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी।

- ii. महाकुंभ के दौरान प्रयाग क्षेत्र के नौ स्टेशनों पर इसी तरह की व्यवस्था की गई थी।
- iii. इन स्टेशनों पर प्राप्त अनुभव के आधार पर, देशभर के 60 स्टेशनों पर जहां समय-समय पर अत्यधिक भीड़ होती है, वहां स्थायी प्रतीक्षालय बनाने का निर्णय लिया गया है।
- iv. प्रायोगिक परियोजनाएँ नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाज़ियाबाद के स्टेशनों पर शुरू हो गई हैं।
- v. इस अवधारणा के अनुसार, अचानक भीड़ बढ़ने पर उन्हें प्रतीक्षा क्षेत्र में नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों को प्लेटफार्मों पर पहुंचने की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब गाड़ियां प्लेटफार्म पर पहुंच जाएं। इससे स्टेशनों पर भीड़ कम होगी।

## 2. पहुंच नियंत्रण:

- i. 60 स्टेशनों पर कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल की शुरुआत की जाएगी।
- ii. पुष्टशुदा आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफार्मों पर सीधे एक्सेस दिया जाएगा।
- iii. बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्री बाहर के प्रतीक्षालय में इंतजार करेंगे।
- iv. सभी अनधिकृत एंट्री प्वाइंट को सील कर दिया जाएगा।

## 3. चौड़े पैदल पार पुल :

- i. 12 मीटर चौड़े (40 फीट) और 6 मीटर चौड़े (20 फीट) मानक पैदल पार पुल के दो नए डिज़ाइन विकसित किए गए हैं। रेंप वाले ये चौड़े पैदल पार पुल महाकुंभ के दौरान जन प्रबंधन में बहुत प्रभावी थे। ये नए मानक के चौड़े पैदल पार पुल सभी स्टेशनों पर स्थापित किए जाएंगे।

## 4. कैमरे:

- i. महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन में कैमरों की बड़ी भूमिका रही। सभी स्टेशनों और आस-पास के क्षेत्रों में गहन निगरानी के लिए बड़ी संख्या में कैमरे स्थापित किए जाएंगे।

## 5. वार रूम:

- i. बड़े स्टेशनों पर वार रूम विकसित किए जाएंगे। भीड़ की स्थिति के दौरान सभी विभागों के अधिकारी वार रूम में काम करेंगे।

## 6. नई पीढ़ी के संचार उपकरण:

- i. भारी भीड़ वाले सभी स्टेशनों पर वॉकी-टॉकी, घोषणा प्रणाली, कॉलिंग प्रणाली जैसे नवीनतम डिज़ाइन के डिजिटल संचार उपकरण स्थापित किए जाएंगे।

## 7. नए डिज़ाइन वाले आईडी कार्ड:

- i. सभी कर्मचारियों और सेवा व्यक्तियों को एक नए डिज़ाइन का पहचान पत्र दिया जाएगा ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही स्टेशन में प्रवेश कर सकें।

## 8. कर्मचारियों के लिए नए डिज़ाइन की वर्दी:

- i. सभी सदस्य कर्मचारियों को नए डिज़ाइन की वर्दीयां दी जाएंगी ताकि उन्हें संकट की स्थिति में आसानी से पहचाना जा सके।

## 9. स्टेशन निदेशक पद का उन्नयन:

- i. सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक वरिष्ठ अधिकारी को स्टेशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सभी अन्य विभाग स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।
- ii. स्टेशन निदेशक को वित्तीय शक्तियां भी दी जाएंगी ताकि वह स्टेशन सुधार के लिए तत्काल निर्णय ले सके।

## 10. क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री:

- i. स्टेशन निदेशक को स्टेशन की क्षमता और उपलब्ध गाड़ियों के अनुसार टिकटों की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार होगा।

इसके अतिरिक्त, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए, सभी हितधारकों को शामिल करके स्टेशन विशेष योजनाएँ बनाई जाती हैं, जिनमें राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी), स्थानीय पुलिस और स्थानीय नागरिक प्रशासन शामिल होते हैं और तदनुसार यात्रियों के अंतः प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए कार्रवाई की जाती है। महत्वपूर्ण गाड़ियों में बिना किसी परेशानी के चढ़ने के लिए प्रारंभिक स्टेशनों पर कतार प्रणाली बनाए रखी जाती है।

भारी भीड़ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और यात्रियों को वास्तविक समय पर सहायता प्रदान करने के लिए राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों को पैदल पार पुल पर भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए तैनात किया जाता है। खुफिया इकाइयाँ (सीआईबी/एसआईबी) और सादे कपड़ों में कर्मचारियों को भीड़ के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए तैनात किया जाता है और उसके अनुसार राजकीय रेल पुलिस/पुलिस को शामिल करके व्यवस्था की जाती है।

अत्यधिक भीड़-भाड़ के दौरान, जब यात्रियों की भारी आवाजाही की संभावना होती है, सिवाय उन लोगों के जो स्टेशन पर बुजुर्ग, अशिक्षित और महिला यात्रियों की सहायता करने के लिए आए हैं और जो रेलवे स्टेशनों पर स्वयं की देखभाल करने की स्थिति में नहीं हैं को छोड़कर क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने पर रोक लगाकर स्टेशनों पर प्रवेश प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।